

न्यायालय वाद संख्या ६७/११	परगनाधिकारी धारा-१४३ उ०प्र०ज०धि० एवं भूव्य०अधिनियम ग्राम मौ०पुर कदीम परगना जगन्नाथाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाँवाद श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल बनाम सारकार	मोदीनगर तहसीलदार, भोदीनगर छाता संख्या ११९/११
इन्स्टीट्यूट		

न्यायालय दस्तावेज़ ५४६/१०-११

प्रस्तुत वाद श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम मौहम्मदपुर कदीम निकट सीकरी कलौं द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवांग शर्मा निवारी ग्राम सीकरी कलौं तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के प्राचीना-पत्र पर तहसीलदार, मोदीनगर की आल्या दिनांक ३-९-११ के आधार पर योजित किया गया तहसीलदार, भोदीनगर द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या १६ खसरा रांख्या ४५३मि० रकबा ०.१६५६ह० व खाता संख्या २६० खसरा नम्बर ४५४मि० रकबा ०.६३५० ह० कुल नम्बर २ कुल रकबा ०.६००६ ह० भूमि में कृषि कार्य बागवानी, मत्स्यालन का कार्य नहीं हो रहा है भूमि ग्रीन बैल्ट में नहीं है अतः धारा १४३ के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की सरतुषि की जाती है।

वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के संबंध में ग्रामसभा/उत्तर प्रदेश सरकार एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नियमानुसार नोटिस जारी किया गया जो वाद तानील शामिल गिराल किये गये गाँवाद विकास प्राधिकरण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि वादग्रस्त भूमि गाँवाद विकास प्राधिकरण के विनियमित हेतु के अंतर्गत पड़ती है प्राधिकरण के क्षेत्राधिकारी ने जाने वाली भूमि के भूउपयोग परिवर्तन करने से मतिन बस्ती को उद्धार मिलाना चाह विकास कार्य पर प्रतिबंध प्रभाव पड़ा अतः म प्राशना-पत्र के आधार पर जाने वाला-पत्र खण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

वादी की व्यक्तिगत सुनिवाइ की गयीतथा पत्रातली का मतीभौति अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शापथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी से कोई वाद नहीं है व न ही किसी से कोई झगड़ा है अतः भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में नहीं हो रहा है इसलिए संदर्भित भूमि को उ०प्र०ज०धि० एवं भू०व्य०अधि० की धारा १४३ के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित है परन्तु स्थानीय विकास प्राधिकरण/निकाय के प्राविधान वाधक न हो तो इस हेतु संदर्भित भूमि में किसी भी प्रकार का विकास व निर्माण तथा भू-उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का मत है कि संदर्भित भूमि को इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्रावेकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास/निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन प्राविधान पूर्व की भौति लागू रहें अकृषिक घोषित किया जाना ही उचित होगा।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी गहोदय द्वारा अपनी बैठक के उपरान्त जारी पत्र संख्या १५२८६ दिनांक २५-३-२००७ के पैरा-४ में निर्देश इस

सर्वे कहते हुए उत्तर प्रदेश उभीकारी दिनांक एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आबादी घोषित किये जाने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जाए। उक्त आदेशों के परिपेक्ष में भी बादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

शासनादेश संख्या 6416 / जी०५-२२५ दिनांक २-८-२००७ वि
द्वासा निर्देशित किया गया है कि सकमणीय भूमिधर वाला अपने खाते वा उल्लं
भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अतंर्गत कुक्कुट पालन भी
है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निर्मित करता है तो परगने का इच्छाज अस्ति० कलेक्टर
रखमेव अथवा प्रार्थना -पत्र पर जाव कर प्रत्यापन कर सकते हैं। इस संघर्ष
में उ०प्र०ज०वि० एवं उ०ब्ब०अ०वि० 1950 की धारा 143 में प्राविधान है कि प्रत्यापन
आदेश की एक प्रति उप निरपेक्ष को भेजी जाए, जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन
एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुए उसे बिना शुल्क और नियत रीति से
निवन्धित कर लेगा। निर्देशित किया गया है कि प्रत्यापन कर स्टाम्प के रूप में
राजस्व का अपवचन रोका जाए। अत राजस्व हित में इसे गैर कृपिय
प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उद्धित प्रतीत होता है।

३८

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम मौहमदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद रिक्त भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 453मि० रकमा 0.1656हौ० व खाता संख्या 260 खसरा नम्बर 454मि० रकमा 0.4350 हौ० कुल नम्बर 2 कुल रकमा 0.6006 हौ० जोकि श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम मौहमदपुर कलीग निकट सीकरी कलों द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवओम शर्मा निः० ग्राम सीकरी कलों तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के नाम दर्शते अधिक संधिः किं वस्तु ह तहसीलदास नोदीनगर जो इन्डिया का १०-४-११ इस आदेश का अंग रहेगी वादी उक्त भूमि में भविष्य में जो वा न काय करेंगे निर्णय से पूर्व स्थानीय निकाय/सक्षम अधिकारी से आपश्वक औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के उपरान्त करेंगे। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदास मोदीनगर को गात्र कागजात में इन्द्राज हेतु एवं उप निवेदक मोदीनगर को ३०प्र०३०विं०३० एवं भ०५००३० वि० की धारा-143 के तहत सहप्रिति नियम-137 में अपेक्षा के अनुरूप इडियन रजिस्टरेशन एक्ट 1908 के तहत निवन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि वह अपना बानुलेख लिपिबद्ध करने के उपरान्त कि यथोक्त नियमित(दैनिक पंजिका) में कर दिया गया हैं, जिस पर उप निवेदक के हस्ताक्षर होगे, न्यायालय को लौटा दें। इस न्यायालय की बाद पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अनिलेखाग्रम में संचित की जाए।

आज यह आदेश मेरे हाथ उस्तादित व दिनांकित कर सुलन्धारालय ने उद्घोषित किया गया।

प्राचीन ग्रन्थ

१९११।
(विजेन्द्र सिंह)
परगनाधिकारी
मोदीनगर।

११८